हरिभूमि
महासमुंद भूमि
रायपुर, बुधवार 08 अप्रैल 2026
सरायपाली | बसना | पिथौरा | बागबाहरा | तुमगांव | खरियार रोड

तापमान
अधिकतम 36.2 डिग्री
न्यूनतम 24.6 डिग्री

12 पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा....

12 आईटीआई में स्वास्थ्य जांच शिविर का...

पानी शुद्ध है या नहीं, बिना जांचे बन रही बर्फ और बिक रही धड़ल्ले से

फैक्ट्रियों के जल स्त्रोतों की जांच नही हुई, मंडरा रहा संक्रमण का खतरा

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

तापमान और गर्मी के बढ़ने के साथ ही शहर में ठंडे पेय पदार्थों और बर्फ की मांग बढ़ने लगी है। शहर से लेकर गांव तक भारी मात्रा में बर्फ बिक रहे हैं। और इसकी शुद्धता की जांच तक नहीं हो पा रही और लोग इसे गटक ले रहे हैं। गंदे और अमानक पानी की जांच के बिना बन रही बर्फ नागरिकों में जलजनित रोगों और संक्रमण का डर बढ़ गया है।

बीच बर्फ की शुद्धता को लेकर शासन प्रशासन स्तर पर कोई ठोस निगरानी न होने के चलते कई स्थानों पर बर्फ का निर्माण और भंडारण किया जा रहा है। लेकिन, इन फैक्ट्रियों में पानी की शुद्धता की जांच अब तक नही की गई है। बता दें कि त्योहारी सीजन में जहां अमला दुकान दुकान सैंपल कलेक्ट करता है। वहीं इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई सामने नहीं आ पाई है। जनस्वास्थ्य के साथ हो रहे इस खिलवाड़ को लेकर लोगों ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इन बर्फ फैक्ट्रियों के पानी के स्त्रोत औ शुध्दता की जांच की जाए।

बाजारों में असुरक्षित रखरखावः नगर के जूस सेंटरों, गन्ने के रस के ठेलों और गोला बेचने वालों के पास बर्फ की सिल्लियां खुले में रखी देखी जा सकती हैं। इन सिल्लियों को अक्सर जूट की बोरियों या पुराने कपड़ों से ढंककर रखा जाता है, जो खुद गंदगी का स्त्रोत हो सकते हैं। परिवहन के दौरान भी बर्फ को बिना किसी सुरक्षा कवर के खुले वाहनों में ले जाया जाता है, जिससे सड़क की धूल और गंदगी बर्फ पर जमा हो जाती है। यही बर्फ सीधे ग्राहकों के गिलास में परोसी जा रही है।

स्वास्थ्य पर मंडराता खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि दूषित बर्फ के सेवन से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। अशुद्ध पानी से बनी बर्फ में ई-कोलाई जैसे बैक्टीरिया हो सकते हैं। इससे उपभोक्ताओं को टाइफाइड और पीलिया (हेपेटाइटिस- ए), पेचिश और डायरिया, गले में संक्रमण और पेट दर्द जैसे समस्या से जूझना पड़ सकता हैं। जिला अस्पताल और निजी क्लीनिकों में पेट दर्द और उल्टी-दस्त के मरीजों की संख्या में धीरे-धीरे इजाफा हो रहा है।

शादियों में भी पानी ठंडा रखने होती है बर्फ की मांग

ग्रामीण इलाकों में शादियों का सीजन शुरू होते ही बर्फ की मांग रहती है। भीषण गर्मी के कारण मेहमानों को ठंडा पानी पिलाने के लिए ग्रामीण भारी मात्रा में बर्फ की सिल्लियां खरीदते हैं। ग्रामीण उसे 400 रुपए तक में खरीद रहे हैं। जिससे अमानक बर्फ की सिल्ली के उपयोग से ठंडा हुए पानी से लोगों की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता हैं।

मांग : किसानों ने लगाई न्याय की गुहार, खरीदी-बिक्री पर रोक लगाने और जांच की मांग

फर्जी दस्तावेज से सरकारी व आदिवासियों की जमीन पर पहले कब्जा, फिर बिक्री

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

जिले के बागबाहरा ब्लॉक के ग्राम पठारीमुड़ा के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टोरेट पहुंचे। उन्होंनें ग्राम पठारीमुड़ा में वर्ष 2016 से लेकर अब तक हुई जमीनों की खरीद फरोख्त की जांच और वर्तमान में हो रही रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग कलेक्टर से की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के कुछ रसूखदार परिवारों द्वारा भू-माफियाओं और राजस्व विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से शासकीय भूमि, घास भूमि और आदिवासियों के कब्जे वाली भूमि को अपने नाम पर दर्ज कराकर बेचा जा रहा है।

शिकायतकर्ता मंगलूराम गोंड, जीवराखन गोंड, पुनऊ राम केंवट, भागीरथी कंवर एवं समस्त पीड़ित किसान, ग्राम पठारीमुड़ा ने बताया कि उनके पूर्वज दशकों से जिन खसरा नंबरों जैसे 660, 502, 549, 427 और 426 पर खेती कर अपना जीवनयापन कर रहे हैं, उन जमीनों को फर्जी दस्तावेज तैयार कर बाहरी लोगों को बेचा जा रहा है। किसानों ने अपनी शिकायत में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि क्षेत्रीय पटवारी और अन्य राजस्व अधिकारियों ने सांठगांठ कर शासकीय रिकॉर्ड में हेरफेर किया है। ग्रामीणों के अनुसार, कई बाहरी व्यक्तियों के नाम पर अवैध रूप से पट्टे जारी कर दिए गए हैं, जबकि वे लोग गांव के निवासी भी नहीं हैं। किसानों ने आरोप लगाया कि सीमांकन के दौरान भी उनके कब्जे वाली भूमि को जबरन दूसरे के खाते में दिखाया जा रहा है।

धमकी और प्रताड़ना से त्रस्त ग्रामीण

कलेक्टर को सौंपे गए पत्र में ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि जमीन मालिक होने का दावा करने वाले लोग और उनके मुख्तियार (प्रतिनिधि) उन्हें बलपूर्वक बेदखल करने की धमकी दे रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी जाती है, जिससे पूरे गांव के किसानों में डर और असुरक्षा का माहौल है।

कठोर कदम उठाने की चेतावनी

ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि इस गंभीर मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई और वर्ष 2016 से हुई फर्जी रजिस्ट्रियों को निरस्त नहीं किया गया, तो वे आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर होंगे। किसानों ने इस मामले की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को भी भेजी है, जिसमें उन्होंने न्याय न मिलने की स्थिति में आत्मदाह तक की बात कही है।

पटवारी पर रिश्वत लेने और रिकॉर्ड में हेराफेरी का आरोप

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

जिला मुख्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में बागबाहरा निवासी मनोज सोनी ने एक पटवारी के खिलाफ गंभीर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज कराई है। आवेदक का आरोप है कि पटवारी ने जमीन का पट्टा बनाने के नाम पर रिश्वत ली और अब रिकॉर्ड में जानबूझकर गड़बड़ी की जा रही है।

बागबाहरा के पुराना थाना पारा निवासी मनोज सोनी ने कलेक्टर को सौंपे आवेदन में बताया कि कोमाखान हल्का नंबर 01 के पटवारी श्रीराम दीवान ने उनके छोटे भाई, खेदू सोनी के कब्जे वाली आबादी जमीन का पट्टा बनाने का झांसा दिया था। आवेदक के अनुसार, पटवारी ने अपने कार्यालय बुलाकर गवाहों के सामने इस काम के बदले 20, 000 रुपये की रिश्वत ली थी। जब काम नहीं हुआ, तो मनोज सोनी ने 17 जुलाई 2024 को जनदर्शन (टोकन नंबर 2120226000357) में इसकी पहली शिकायत की। शिकायत के बाद 27 फरवरी 2026 को राजस्व निरीक्षक दौलत सिंह ठाकुर और चार पटवारियों की टीम ने मौके पर जाकर जांच की थी। जांच के दौरान बनाए गए पंचनामा में उपस्थित पंचों और परिवार के सदस्यों ने पुष्टि की कि संबंधित जमीन खसरा नंबर 333/28, रकबा 603.31 वर्ग मीटर पिछले 30 वर्षों से खेदू सोनी के कब्जे में है और बंटवारे में उन्हीं के हिस्से में आई है। राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में रिश्वत के आरोपों की जांच के लिए उच्च अधिकारियों को बयान लेने और आगे की कार्रवाई के लिए उचित ठहराया था। आवेदक मनोज सोनी का कहना है कि अब तक रिश्वतखोरी के मामले में पटवारी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। उल्टा, पटवारी श्रीराम दीवान ने नियमों को ताक पर रखकर उसी जमीन के सरकारी रिकॉर्ड में परिवार के उन सदस्यों के नाम भी दर्ज कर दिए हैं, जो वर्षों से दूसरे शहरों में रह रहे हैं। आवेदक का आरोप है कि पटवारी ने अन्य लोगों से पैसे लेकर जानबूझकर रिकॉर्ड में हेराफेरी की है ताकि मामले को उलझाया जा सके। मनोज सोनी ने कलेक्टर से निवेदन किया है कि रिश्वत लेने वाले पटवारी के खिलाफ सख्त विभागीय कार्रवाई की जाए। आबादी जमीन को उसके वास्तविक हकदार खेदू सोनी के नाम पर दर्ज करने के आदेश दिए जाएं। पटवारी द्वारा रिकॉर्ड में की गई अवैध प्रविष्टियों की सूक्ष्म जांच कराई जाए।

महासमुंद शहर कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी घोषित, संगठन को मिलेगी नई मजबूती

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार और जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष द्वारकाधीश यादव के मार्गदर्शन में शहर कांग्रेस कमेटी महासमुंद की बहुप्रतीक्षित कार्यकारिणी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। नई टीम में सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के बीच एक सटीक संतुलन बनाने नजर आ रहा है। शहर अध्यक्ष गुरमीत चावला ने कार्यकारिणी की सूची जारी करते हुए कहा कि नई टीम पूरी ऊर्जा के साथ स्थानीय जनमुद्दों को उठाएगी और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाएगी। 31 सदस्यीय कार्यकारिणी के प्रमुख पदाधिकारियों में उपाध्यक्षः तुलसी

साहू, मुस्ताक खान विक्की, डॉ तरुण साहू, महामंत्री निर्मल जैन, अजय थवाईत, मेहुल सूचक, देवेश शर्मा, सचिव राजेश नेताम, गोपी तारक, अनीश राजवानी, राहुल लालवानी, कोषाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह धनवा, कार्यकारिणी सदस्य पार्षद जय देवांगन, राजेश डडसेना, ओमिन कागजी को नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति पर जिलाध्यक्ष द्वारकाधीश यादव, पूर्व प्रदेश प्रभारी महामंत्री अमरजीत चावला, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ रश्मि चंद्राकर, पूर्व विधायक विनोद चंद्राकर, पूर्व जिलाध्यक्ष आलोक चंद्राकर, नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू समेत प्रदेश और जिला स्तर के वरिष्ठ नेताओं ने हर्ष जताया है।

ग्रामीण ब्लाक कांग्रेस कमेटी में दिवंगत कार्यकर्ता को मिला स्थानः जिले के सभी ब्लाकों में स्थानीय कांग्रेस कमेटी की घोषणा कर दी गई है। ग्रामीण ब्लाक कांग्रेस कमेटी की घोषित सूची में पार्टी के दिवंगत कार्यकर्ता का भी नाम शामिल होने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि परसवानी निवासी ओंकार चंद्राकर जो दिवंगत हो चुके हैं उन्हें ब्लाक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की सूची में बतौर कार्यकारिणी सदस्य शामिल किया गया है। मामले में सूची तैयार करने वालों और सूची भेजने वालों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं।

दुकान बंद होने के बाद शराब नहीं दी तो सेल्समैन से मारपीट, अब तक दर्ज भी नहीं हुई एफआईआर

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

शराब दुकान के बंद होने के बाद भी जबरिया शराब मांगने और शराब नही देने पर दुकान कर्मी के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। खास बात तो यह है कि पीड़ित द्वारा की गई शिकायत के बाद भी संबंधित आरोपियों के खिलाफ अब तक प्राथमिकी दर्ज नही की गई है जबकि पीड़ित ने घटना की सीसी टीवी फुटेज भी कोतवाली के सुपुर्द की है।

शहर के सुभाष नगर वार्ड नंबर 25 निवासी अभिजीत बोस (39 वर्ष) ने पुलिस को बताया हैकि वह सितली नाला स्थित अंग्रेजी शराब दुकान में विक्रेता के रूप में कार्यरत हैं। घटना 2 मई की रात करीब 10 बजे की है। जिसके अनुसार, जब वे और उनके साथी कर्मचारी दुकान बंद कर रहे थे, तभी दो लोग वहां पहुंचे। दुकान बंद होने के बावजूद शराब की मांग करने और शराब न मिल पाने के चलते दोनों ने अभिजीत के साथ विवाद शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने कर्मचारी को गालियां दीं और मारपीट की।

पीड़ित अभिजीत बोस ने बताया है कि आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। शिकायत में कहा गया है कि यदि मौके पर शराब दुकान के अन्य कर्मचारी मौजूद नहीं होते, तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। अन्य कर्मचारियों के हस्तक्षेप के बाद ही मामला शांत हुआ, जिसके बाद पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते

हुए थाने में आवेदन दिया। जिसमें पीड़ित के साथ अन्य कर्मचारियों ने भी घटना की पुष्टि की है।

विक्रेताओं में भय व्याप्त

पीड़ित ने नामजद शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन अब तक पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की। जब कर्मचारी और प्रत्यक्षदर्शी गवाह मौजूद हैं, तो पुलिस जांच के नाम पर समय क्यों ले रही है। सरेराह दुकान बंद करते समय कर्मचारी के साथ हुई इस घटना ने अन्य विक्रेताओं में भी डर का माहौल है।

कर्मचारियों में आक्रोश

सितली नाला शराब दुकान के कर्मचारियों का कहना है कि यदि ड्यूटी के दौरान उनके साथ ऐसी अभद्रता और हिंसा होगी और पुलिस रक्षा नहीं करेगी, तो वे असुरक्षित महसूस करेंगे। फिलहाल, पीड़ित और उनके साथी पुलिस के उच्च अधिकारियों से मामले में संज्ञान लेने और जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई करने की प्रतीक्षा में हैं।

कोटादादर प्राथमिक शाला में कक्षा 1-2 के छात्र-छात्राएं वार्षिक परीक्षा से वंचित

हरिभूमि न्यूज ⏭ पिथौरा (ग्रामीण)

विकासखंड अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला कोटादादर में वार्षिक परीक्षा के दौरान लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां कक्षा पहली और दूसरी में अध्ययनरत विद्यार्थियों की वार्षिक परीक्षा आयोजित नहीं की गई, जिससे दोनों कक्षाओं के छात्र परीक्षा से वंचित रह गए।

मिली जानकारी अनुसार बीते 6 अप्रैल को कक्षा 1 के लिए हिंदी, कक्षा 2 के लिए अंग्रेजी, कक्षा 3 के लिए गणित तथा कक्षा 4 के लिए हिंदी विषय की परीक्षा निर्धारित थी।

जिसमें कक्षा तीसरी और चौथी की परीक्षा तो नियमित रूप से संपन्न कराई गई, लेकिन कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं ली गई। विद्यालय में कक्षा पहली में 12 एवं कक्षा दूसरी में 14 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं, जो इस लापरवाही के कारण परीक्षा से वंचित रह गए। इससे उनके शैक्षणिक मूल्यांकन पर भी असर पड़ने की आशंका है। गौरतलब है कि विद्यालय में कुल तीन शिक्षक पदस्थ हैं, जिनमें प्रधान पाठक रेहाना बानो, सहायक शिक्षक श्याम कुमार पटेल एवं सहायक शिक्षक उषा दीवान शामिल हैं।

जानकारी के मुताबिक प्रधान पाठक रेहाना बानो की ड्यूटी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मोहंदा में पर्यवेक्षक के रूप में लगी हुई थी। ऐसे में विद्यालय में परीक्षा संचालन की जिम्मेदारी सहायक शिक्षक श्याम कुमार पटेल को सौंपी गई थी। आरोप है कि उनकी लापरवाही के चलते ही कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की परीक्षा नहीं ली गई। इस घटना से न केवल बच्चों का शैक्षणिक नुकसान हुआ है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इस संबंध में सहायक शिक्षक श्याम कुमार पटेल ने बताया कि भूलवश परीक्षा नहीं ली जा सकी।

इस संबंध में पिथौरा विकासखंड शिक्षा अधिकारी लक्ष्मी डड़सेना का कहना है कि संबंधित शिक्षक को परीक्षा नहीं लेने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी जानकारी दे दी गई है।

खबर संक्षेप

अस्पताल के सामने से बाइक चोरी

महासमुंद। अस्पताल के सामने से बाइक चोरी के मामले में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध सिटी कोतवाली में जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को ईश्वर सेन निवासी नयापारा ने बताया कि 01 मार्च को वह अपनी मोटर सायकल टीवीएस एक्सेल 100 क्र सीजी 06 एचडी 9982 में मछली बेचने ग्राम पचेड़ा गया था। शाम को वापस आने पर उसने सोहम अस्पताल के सामने अपनी बाइक को खड़ी किया था। थोड़ी देर बाद वापस आने पर देखा कि बाइक उक्त स्थान पर नहीं थी। मामले की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 303(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार की मौत

महासमुंद। ग्राम बिरकोनी के एक ढाबा के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से कार सवार की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक अमन साहू पिता निमई साहू (27 साल) नोवामुंडी वार्ड नं 05 थाना नोवामुंडी जिला पश्चिम सिंगभूम, झारखंड के मर्ग मामले की जांच किया गया। पुलिस ने बताया कि 03 अप्रैल को मृतक अपने दोस्तों एवं चचेरे भाई के साथ शादी का सामान खरीदने रायपुर गया था। सामान खरीदने के बाद 5 अप्रैल को वापस रायपुर से नोवामुंडी झारखंड के लिए अर्टिगा कार क्रमांक जेएच 05 सीपी 5207 से जा रहा रहा था। रात्रि करीबन 10.30 बजे ग्राम बिरकोनी एनएच 53 रोड महाराजा ढाबा के पास के अज्ञात वाहन के चालक द्वारा अपने वाहन को तेजी एवं लापरवाही पूर्वक चलाते हुये मृतक के कार को दाहिने साईड से ठोकर मारकर एक्सीडेंट कर दिया, जिससे अमन साहू एवं उसके दोस्त विश्वजीत, सिपुल अपट, विवेक करवा एवं सुधीर नाग को चोटें आईं। गले में गंभीर चोट आने की वजह से अमन साहू की मौत हो गई। मामले में आरोपी अज्ञात वाहन चालक के विरूद्ध धारा 281, 125-ए, 106(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।

महिला से मारपीट

महासमुंद। महिला से मारपीट करने के मामले में सरायपाली थाने में आरोपी मां-बेटे के विरूद्ध जुर्म दर्ज किया गया है। पुलिस को सलीमा श्रीवास निवासी ग्राम पलसाभाडी ने बताया 06 अप्रैल की शाम 7.30 बजे घर में सब्जी काट रही थी, तभी उसका पड़ोसी अंकित बारिक पिता ऋषिकेश बारिक उसके घर के सामने आकर पुरानी रंजिश को लेकर गालियां देने लगा, जब वह घर से बाहर निकली तो आरोपी ने पत्थर से मारा। इसी दौरान आरोपी की मां क्रिस्टिना बारिक भी आई और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। मामले की रिपोर्ट पर आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(2) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

बाइक सवारों से देशी शराब बरामद

महासमुंद। सांकरा पुलिस ने बाइक में सवार दो लोगों के कब्जे से देशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलने के बाद गुरु घासीदास चौक सांकरा NH 53 रोड के पास एक बाइक को रोका गया। जिसमें दो लोग सवार थे। जिन्होंने अपने नाम सुजल प्रधान पिता गंगाधर प्रधान (35 साल) देवलगढ़ थाना बसना और छबीलाल बंजारा पिता स्व. चंदन सिंह बंजारा (24 साल) देवलगढ़ थाना बसना होना बताया। मामले में इन लोगों के कब्जे से शेरा देशी प्लेन शराब 35 पौवा कीमत 2800 रुपए व बाइक को बरामद किया गया। आरोपियों के विरूद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई।

WE ARE HIRING
Job Opening
CIRCULATION ASSISTANT MANAGER
Position : Circulation Assistant Manager - 2 Post
Location : Raipur City
We are looking for a dynamic, Target Oriented and motivated Circulation Assistant to Join our team.
Qualifications :
- MBA (Marketing) from a recognized institution
- 3-5 Years of relevant experience in circulation Department
- Age 25 to 30 Years
Responsibilities :
- Manage circulation and distribution of publications
- Handle customer queries
- Maintain accurate circulation records
How to Apply
Interested candidates may send their resume to Email : inhnewshr@gmail.com
Last Date to Apply : 10 April 2026
हरिभूमि inh Opp. Pujari Park, Dhamtari Road, Tikrapara, Raipur

खबर संक्षेप

3 माह का राशन प्रदान कर सरकार ने दी गरीबों को राहत : भाऊराम

महासमुंद। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गरीबों को 3 महीने का राशन एक मुश्त दिए जाने के निर्णय का स्वागत करते हुए भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष व पार्षद भाऊ राम साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है।

भाऊराम ने कहा कि अप्रैल 2026 में सरकार द्वारा राशन कार्ड धारकों को 3 महीने (अप्रैल, मई, जून) का राशन एक साथ देने के निर्णय से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। सरकार का यह कदम बीपीएल हितग्राहियों को राशन दुकानों के बार-बार चक्कर लगाने से बचाएगा, समय की बचत करेगा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सुशासन में प्रदेश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को खाद्य सुरक्षा प्रदान किया जा रहा है। सरकार ने शासकीय उचित मूल्य के दुकानों में चावल उत्सव का शुभारंभ कर बीपीएल हितग्राहियों को एक मुश्त चावल उपलब्ध करा रही है। सरकार की यह पहल ग्रीष्म ऋतु में हितग्राहियों को बार बार राशन दुकानों के चक्कर लगाने से तथा तेज गर्मी से राहत प्रदान करेगी। भाजपा सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के गरीब बीपीएल हितग्राहियों के हित में लगातार निर्णय लेकर राहत प्रदान किए जाने से प्रदेशवासियों में हर्ष का माहौल है।

सरायपाली सीएचसी में उत्साहपूर्वक मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस

सरायपाली। जिले के स्व मोहनलाल चौधरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरायपाली में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस उत्साह एवं जागरूकता के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नागेश्वर राव के निर्देशन में सभी के स्वास्थ्य और बेहतर भविष्य के लिए प्रतिबद्ध संदेश के अनुरूप तथा खंड चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुणाल नायक के मार्गदर्शन में किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां हुईं। खंड विस्तार प्रशिक्षण अधिकारी टीआर धृतलहरे ने अपने संबोधन में बताया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना एवं बीमारियों की रोकथाम के प्रति सजग बनाना है। उन्होंने कहा कि नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित आहार, स्वच्छता तथा योग-व्यायाम को अपनाकर कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा उपस्थित लोगों को स्वच्छता, पोषण, टीकाकरण एवं जीवनशैली से संबंधित जानकारी दी गई। कार्यक्रम में स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ एवं अन्य कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी रही। सभी ने मिलकर स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया। कार्यक्रम का समापन लोगों को स्वयं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने तथा दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने के संदेश के साथ किया गया। इस अवसर पर मितानिन कार्यक्रम से जिला मितानिन समन्वयक जागृति बरेठा, ब्लॉक समन्वयक रुदना राणा, पार्वती चौधरी, स्वस्थ पंचायत समन्वयक लोचना सोना, रामबती बारिक सहित विकासखंड सरायपाली के सभी मितानिन प्रशिक्षक उपस्थित रहे।

जनगणना में ओबीसी कॉलम नहीं होना अन्याय

रायपुर। आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष उत्तम जायसवाल ने आगामी डिजिटल जनगणना के लिए निर्धारित 33 बिंदुओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से कॉलम नहीं होने पर पिछड़ा वर्ग की उपेक्षा किए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए दोहरा मापदंड अपना रही है। पिछड़े समाज के विकास की बात करने वाली केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की साय सरकार आज इस मामले में असहाय नजर आ रही है। सरकार पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक बनाकर रखना चाहती है। अन्य वर्ग के लिए स्पष्ट कॉलम दिया गया है, लेकिन ओबीसी वर्ग की गणना के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

आयोजन : छग टीचर्स एसोसिएशन की रायपुर में हुई प्रांतीय महासभा

छग टीचर्स एसोसिएशन ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन की मांग को लेकर भरी हुंकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा रायपुर में प्रांतीय महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रायपुर उत्तर विधायक पुरंदर मिश्रा रहे। अध्यक्षता एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा ने की। महासभा में प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, महासमुंद जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी एवं प्रदेशभर से आए पदाधिकारियों और शिक्षकों ने प्रथम नियुक्ति से पेंशन की एक सूत्रीय मांग को लेकर जोरदार हुंकार भरी।

मुख्य अतिथि पुरंदर मिश्रा ने शिक्षकों की मांगों को गंभीरता से सुना और आश्वस्त किया कि वे पेंशन संबंधी इन जायज मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। उन्होंने शीघ्र ही एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात मुख्यमंत्री से कराने का भी भरोसा दिलाया। प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, जिलाध्यक्ष नारायण चौधरी ने मुख्य अतिथि को मांग पत्र सौंपते हुए सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षकों की जीरो पेंशन व्यवस्था की व्यथा साझा की। मांग पत्र में प्रमुखता से प्रथम नियुक्ति से गणना- वर्तमान में पेंशन के लिए सेवा अवधि की गणना संविलियन तिथि (1 जुलाई 2018) से की जा रही है, जिससे 2028 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले एलबी संवर्ग के शिक्षक पुरानी पेंशन से वंचित हो रहे हैं। अतः पुरानी पेंशन के लिए पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) की गणना की जाए। 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष की अर्हकारी सेवा में पूर्ण पेंशन (अंतिम वेतन का 50 प्रतिशत) का प्रावधान किया जाए। उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं (जैसे रमेश चंद्रवंशी एवं अन्य) में दिए गए निर्देशों का उल्लेख किया गया, जिसमें पेंशन को स्थगित पारिश्रमिक माना गया है और संविलियन से पूर्व की दीर्घकालीन सेवाओं को नजरअंदाज न करने की बात कही गई है। इन आधारों पर पूर्व सेवा अवधि को पेंशन योग्य सेवा मानते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन की गणना किया जाए। शिक्षकों की सेवा अवधि 65 वर्ष तक किए जाने, प्रदेशभर के शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान वेतनमान प्रदान करने, प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठक मिडिल स्कूल, शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक स्कूल के पदों पर पदोन्नति करने, विभागीय टीईटी परीक्षा आयोजित करने, विभागीय डीएड व बीएड परीक्षा की व्यवस्था करने की मांगों पर कार्ययोजना बनाते हुए विशेष मंथन प्रदेशभर के प्रांतीय पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, पदाधिकारी व संकुल पदाधिकारी ने की है। साथ में इन विषयों की प्राप्ति के लिए निरंतर रणनीति आधारित कार्य करने का निर्णय लिया गया है।

स्कूल शिक्षा मंत्री ने अपने बयान में कहा है कि सरकार टीईटी के मामले का रास्ता निकालेगी, शिक्षकों की मांग पर पूरी गंभीरता के साथ विचार हो रहा है। हम किसी का नुकसान नहीं होने देना चाहते, विभाग में इसे लेकर विचार-विमर्श हो रहा है।

महासभा में शिक्षा मंत्री के बयान को सकारात्मक बताते हुए स्वागत किया गया। सहायक शिक्षक, शिक्षक व व्याख्याता जो केवल डीएड या समकक्ष योग्यता रखते हैं, उन सभी के लिए एनसीटीई के नियमानुसार कोर्स निर्धारण कर 6 माह के बीएड कोर्स शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इसके लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ओपन बोर्ड से बीएड पत्राचार का अनुबंध कर संपर्क क्लास पूर्ण कर शीघ्र बीएड पाठ्यक्रम पूर्ण कराया जाए। महासभा में महासमुंद से सुधीर प्रधान प्रदेश संयोजक, नारायण चौधरी जिलाध्यक्ष, महेंद्र चौधरी ब्लॉक अध्यक्ष पिथौरा, एनके तिवारी, नंदकुमार साहू, प्रदीप वर्मा, खिलावन वर्मा, पवन कुमार साहू, मनीष अवसरिया, देवेंद्र चंद्राकर, घनश्याम चक्रधारी, जितेंद्र साहू, गौरी शंकर पटेल, अनूप नायक, राजेंद्र पांडे आदि उपस्थित रहे।

बागबाहरा में 40 लाख की लागत से होंगे निर्माण कार्यों, भूमिपूजन

बागबाहरा। नगर पालिका परिषद् बागबाहरा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में 40 लाख लागत से बन रहे विकास कार्यों का भूमिपूजन नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल व पार्षद के हाथो हुआ। वार्ड क्र. 02 व्यापारी तालाब में सामुदायिक भवन से राजकुमार पटेल घर तक सीसी रोड निर्माण 5.61 लाख,वार्ड 02 व्यापारी तालाब में जैन इलेक्ट्रानिक से जगत राम साहू घर तक सीसी रोड मरम्मत 7.35 लाख, वार्ड 07 में बस स्टैंड से फिरोज खान घर तक सीसी रोड निर्माण 9.96 लाख, वार्ड 13 में नयकिन तालाब से राजकुमार महानंद घर तक आर.सीसी नाली निर्माण 8.11 लाख, वार्ड 14 में राजकुमार किराना स्टोर्स से बेलो बाई यादव के घर तक सीसी रोड निर्माण 4.71 लाख,वार्ड 14 में आनंद साहू घर से अनिल अग्रवाल घर तक आरसीसी नाली निर्माण 4.05 लाख, भूमिपूजन विधि-विधान के साथ व मंत्रो उच्चारण के साथ हुआ

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष खिलेश्वरी ताम्रध्वज बघेल ने कहा कि आज 40 लाख के लागत के विभिन्न वार्डों में विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। नगर में सड़क और आरसीसी नाली के निर्माण से मोहल्लेवासियों को जल निकासी की समस्या से राहत मिलेगी। साथ ही सड़क बनने से आवागमन सुगम और सुविधाजनक होगा। नगर में विकास कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। नगर की बेहतरी और निवासियों की सहूलियत के लिए हर वार्ड में लगातार काम चल रहा है। पालिकाध्यक्ष श्रीमती बघेल ने कहा कि नगर का चहुंमुखी विकास उनकी पहली प्राथमिकता है। शहर में जहां भी नाली और सड़क की आवश्यकता है, यह कार्य प्राथमिकता से कराया जा रहा है। पालिकाध्यक्ष ने ठेकेदार से कहा कि निर्माण गुणवत्ता के साथ कराएं। इस अवसर पर नपा उपाध्यक्ष देवेश साहू, पार्षद सविता दीवान, मंता यादव, थानूराम पांडे, शिवा जगत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी गिरीश चंद्रा सहित नगर पालिका के कर्मचारी, वार्डवासी उपस्थित थे।

जिले के उचित मूल्य दुकानों में मनाया गया चावल उत्सव

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

राज्य शासन निर्देश एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के मार्गदर्शन में जिले के शासकीय उचित मूल्य दुकानों में चावल उत्सव का आयोजन उत्साहपूर्वक किया गया। इस अवसर पर प्रत्येक दुकान में उत्सव के रूप में खाद्यान्न वितरण किया गया, जिससे हितग्राहियों को समय पर एवं सुगमता से राशन प्राप्त हुआ।

चावल उत्सव के दौरान उचित मूल्य दुकानों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में चावल वितरण का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में राशन कार्डधारी हितग्राही, निगरानी समिति के सदस्य, मितानिन, स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि तथा राजस्व एवं खाद्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान हितग्राहियों ने कहा कि शासन द्वारा तीन माह का चावल वितरण से राशन की चिंता से मुक्ति मिली है।

जिला प्रशासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अप्रैल, मई एवं जून माह के लिए चावल भंडारण अंतर्गत अप्रैल माह का शत-प्रतिशत भंडारण पूर्ण कर लिया गया है। इसी तरह मई माह के लिए 221 दुकानों तथा जून माह के लिए 39 दुकानों में अग्रिम भंडारण किया जा चुका है। कलेक्टर लंगेह ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी पात्र हितग्राहियों को समय पर एवं पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाए, ताकि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे।

कलेक्टर ने ली जिला पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति की बैठक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

जिला पशु बाजार मॉनिटरिंग समिति की बैठक कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में जिले में संचालित पशु बाजारों के सुचारू, व्यवस्थित एवं नियमानुसार संचालन को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू सहित समित के सदस्य एवं जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर लंगेह ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों, मुख्य नगरपालिका अधिकारियों एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पशु बाजारों के संचालन में नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें तथा पशु बाजार विनियमन नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करें। कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई पशु बाजार निर्धारित नियमों के अनुरूप संचालित नहीं पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने विकासखंड स्तर पर स्थानीय प्राधिकारियों के माध्यम से पशु बाजार समितियों के गठन के निर्देश दिए गए हैं, जो प्राप्त आवेदनों की जांच कर पात्र पाए जाने पर प्रस्ताव जिला मॉनिटरिंग समिति को प्रस्तुत करती है। जिला समिति द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण कर नियमानुसार पंजीयन एवं संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है। बैठक में बताया गया कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना के तहत लागू पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशु बाजार विनियमन) नियम, 2017 के अंतर्गत जिले में जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति का गठन किया गया है। यह समिति पशु बाजारों के संचालन हेतु पंजीयन एवं अनुमति प्रदान करती है।

आरटीई के तहत प्रवेश न देने वाले निजी विद्यालयों की मान्यता होगी रद्द

शासन का कहना- छग में आरटीई प्रतिपूर्ति राशि दूसरे राज्यों से बेहतर

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत निजी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों की फीस राशि बढ़ाने की मांग कर रहे विद्यालयों को लेकर शासन ने कड़ा रूख अपनाया है।

■ आरटीई फीस बढ़ाने की मांग कर रहे हैं प्रदेश के निजी विद्यालय

शासन ने स्पष्ट किया है कि जो विद्यालय आरटीई के अंतर्गत दाखिला नहीं देंगे, उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। गौरतलब है, आरटीई प्रतिपूर्ति राशि नहीं बढ़ाने जाने की स्थिति में निजी स्कूलों ने शासकीय कार्यों में असहयोग करने का निर्णय लिया है। शासन के मुताबिक, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निजी स्कूलों को नर्सरी या कक्षा 1 में 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना अनिवार्य है। इसके बदले राज्य सरकार प्रति बच्चा व्यय के आधार पर स्कूलों को प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान करती है। यह राशि सरकारी स्कूल में प्रति बच्चे पर होने वाले खर्च या निजी स्कूल की वास्तविक फीस (दोनों में से जो भी कम हो) के आधार पर निर्धारित की जाती है। छत्तीसगढ़ में शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि कई पड़ोसी राज्यों की तुलना में बेहतर या उनके समकक्ष है।

अन्य राज्यों में इतना भुगतान

प्रदेश में वर्ष 2011-12 से ही पहली से पांचवीं कक्षा तक 7000 रूपए और छठवीं से आठवीं कक्षा तक 11 हजार 400 रूपए वार्षिक प्रतिपूर्ति राशि निर्धारित है। तुलनात्मक रूप से देखें तो मध्य प्रदेश में 4,419 रूपए बिहार में 6,569 रूपए, झारखंड में 5,100 रूपए और उत्तर प्रदेश में 5,400 रूपए वार्षिक दिए जाते हैं। यद्यपि ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह राशि अधिक है, किंतु समग्र मूल्यांकन में छत्तीसगढ़ की प्रतिपूर्ति राशि संतुलित और उचित है।

3.63 लाख छात्र आरटीई के

वर्तमान में राज्य के 6,862 निजी विद्यालयों में आरटीई के माध्यम से लगभग 3,63,515 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस वर्ष भी कक्षा पहली की लगभग 22,000 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया जारी है। चूंकि सभी निजी विद्यालयों को आरटीई अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही मान्यता दी गई है, अतः यह उनकी वैधानिक जिम्मेदारी है कि वे निर्धारित सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें। यदि कोई निजी विद्यालय आरटीई के तहत प्रवेश देने से इंकार करता है या प्रक्रिया में व्यवधान डालता है, तो राज्य शासन उनके विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा। इसमें विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान शामिल है।

डीएड अभ्यर्थियों ने दंडवत होकर की प्रार्थना

रायपुर। डीएड अभ्यर्थियों ने सोमवार को सहायक शिक्षकों के 2300 खाली पड़े पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अनूठा प्रदर्शन किया। नवा रायपुर के तूता स्थित धरनास्थल पर प्रदेश के 14 कैबिनेट मंत्रियों के मुखौटे के सामने दंडवत प्रणाम करते हुए पूजा-अर्चना की। साथ ही मंत्रियों की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना की। छत्तीसगढ़ डीएड अभ्यर्थी संघ के आव्हान पर प्रदेशभर के चयनित डीएड अभ्यर्थी नवा रायपुर के तूता स्थित धरनास्थल पर 104 दिनों से अलग-अलग तरीके से शासन का ध्यान आकर्षित कराने आंदोलन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन आमरण अनशन के जरिए वे अपने लंबित मांग को शासन तक पहुंचाने धरनास्थल पर डटे हुए हैं। आंदोलन कर रहे डीएड अभ्यर्थियों का कहना है यदि जल्द ही उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई तो वे आगे बड़े स्तर पर आंदोलन करने बाध्य होंगे।

ये कैसा वर्कआर्डर...पुराना एसपी भवन ढहाए बिना कम्पोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

राजधानी रायपुर के कलेक्टोरेट परिसर में पांचमंजिला कम्पोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू हो गया है, लेकिन वर्कआर्डर के अनुसार, जितनी जमीन पर बिल्डिंग का निर्माण शुरू किया जाना था, उसकी आधी जमीन पर ही कार्य शुरू हो पाया है। पुराने एसपी भवन को अब तक तोड़ा नहीं गया है, जबकि जारी वर्कऑर्डर के अनुसार उक्त भवन को तोड़े जाने के बाद ही एक साथ निर्माण कार्य शुरू होना था। इधर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों का कहना है कि एसपी कार्यालय की शिफ्टिंग हो चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ अन्य अधिकारियों के दफ्तर इस भवन में लग रहे हैं। भवन पूरी तरह खाली होने पर ही उसे तोड़ा जा सकेगा। कलेक्टोरेट परिसर में कलेक्टोरेट और एसपी कार्यालय के लिए पांचमंजिला कम्पोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य वर्ष 2023 से प्रस्तावित है। इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए कांग्रेस शासनकाल में मंजूरी दी गई थी। इसके बाद से इस बिल्डिंग के निर्माण में लगातार बाधा आ रही है। मंजूरी के बाद विधानसभा चुनाव, उसके बाद लोकसभा और फिर नगरीय निकाय चुनाव के कारण इस बिल्डिंग का निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था।

■ पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने कहा- भवन पूरी तरह खाली नहीं, इसलिए तोड़ा नहीं गया

एक वर्ष से अधिक समय लगने की संभावना

सूत्रों के अनुसार वर्कऑर्डर में एजेंसी को कंपोजिट बिल्डिंग का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए डेढ़ से दो वर्ष का समय दिया है। इसमें बारिश सीजन के महीने भी शामिल हैं, लेकिन एसपी भवन को तोड़े बिना बिल्डिंग निर्माण का कार्य समयसीमा में खत्म होना संभव प्रतीत नहीं होता। सूत्रों की मानें तो निर्माण कार्य पूर्ण होने में दिए गए समय के अलावा और एक वर्ष या उससे भी अधिक समय लगने की संभावना है।

लेटलतीफी के कारण बढ़ी लागत

सूत्रों की मानें तो 29 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से कंपोजिट बिल्डिंग के निर्माण का ठेका वर्ष 2023 में दिया गया था। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद वित्त विभाग से दोबारा इस बिल्डिंग के निर्माण के लिए बजट को स्वीकृति दी गई। हालांकि टेंडर जिस एजेंसी को मिला था, उसे बरकरार रखा गया।

वर्कऑर्डर जारी हुए कई महीने बीते, भवन अब तक टूटा नहीं

पांचमंजिला कम्पोजिट बिल्डिंग के निर्माण के लिए वर्कऑर्डर जारी हुए कई महीने बीत चुके हैं। इसके बावजूद एसपी भवन को तोड़ा नहीं गया है। इधर पीडब्ल्यूडी विभाग ने जिस एजेंसी को कंपोजिट बिल्डिंग निर्माण का ठेका दिया है, उसने एसपी भवन तोड़े बगैर ही कम्पोजिट बिल्डिंग का निर्माण शुरू कर दिया है। इसके लिए एसपी भवन के पीछे और कोर्ट की तरफ खाली जमीन पर खुदाई करने के साथ कॉलम लगाने का कार्य लगभग पूरा कर लिया है।

पुलिस कमिश्नरेट के एनएटीएफ अजाक सहित 15 थानों के टीआई बदले ज्यादातर लाइन से थाने पदस्थ

रायपुर। पुलिस कमिश्नरेट के 21 थानों में से 13 थानों के टीआई का पुलिस कमिश्नर ने तबादला आदेश जारी किया है। साथ ही पांच ट्रैफिक थानों के टीआई का पुलिस कमिश्नर ने तबादला आदेश जारी किए हैं।

पुलिस कमिश्नर ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से 22 टीआई के तबादला आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के मुताबिक सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई पदस्थापना में कार्यभार ग्रहण करने पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस रक्षित केंद्र से जिन टीआई को थाने की जिम्मेदारी दी गई है, उनमें जितेंद्र जायसवाल को खमतराई, अजय झा को तेलीबांधा और शक्ति सिंह को मौदहापारा, रितेश मिश्रा आजाद चौक, गौतमचंद्र गवड़े डीडीनगर, दीपेंद्र कुमार सैनी देवेंद्र नगर, गगन बाजपेयी कबीर नगर, अजरुद्दीन राजेंद्र नगर, राजेश कुमार मरई टिकरापारा थाने के टीआई बनाए गए हैं।

सम्मानजनक मृत्यु और संस्कार का अधिकार बहाल करा रहा हाईकोर्ट, मुक्तिधामों के लिए 188 करोड़ जारी

हरिभूमि न्यूज ▶▶| रायपुर

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए मुक्तिधामों की बदहाली सुधारने के संबंध में कहा था कि भारतीय अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकारों में सम्मानजनक मृत्यु और संस्कार का अधिकार शामिल है।

यद्यपि पूरे राज्य में मुक्तिधाम वह स्थान है, जिसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है, का उल्लेख करते हुए पंचायतों-निकायों में स्थित मुक्तिधाम की व्यवस्था सुधार करने के निर्देश दिए गये थे। हाईकोर्ट के इस आदेश के पालन के लिए राज्य के 49 निकायों में मुक्तिधामों की बदहाली सुधारने के लिए शासन ने 188 करोड़ रुपए की पहली किस्त 49 नगरीय निकायों को जारी की है। इस प्रक्रिया से हाईकोर्ट की पहल पर सम्मानजनक मृत्यु और संस्कार के अधिकार की बहाली नजर आ रही है।

सरकार ने जारी की 188 करोड़ की पहली किस्त : हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 49 नगरीय निकायों के मुक्तिधामों की व्यवस्था सुधारने के लिए 188 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी कर दी है। इसके साथ ही जो शर्तें रखी गई हैं, उसमें प्रमुखता से कहा गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का परिपालन करना सुनिश्चित करें।

आदर्श मुक्तिधाम में हों ये सुविधाएं : नगरीय निकायों में मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाकर परिसर की आवश्यक साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें। समय-समय पर मुक्तिधाम परिसर की साफ-सफाई, आवश्यक सफाईकर्मी लगाकर की जाए। नगरीय निकाय द्वारा इसका नियमित पर्यवेक्षण किया जाए। मुक्तिधाम परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण के माध्यम से ग्रीन फेंसिंग लगाया जाना सुनिश्चित करें। जिन निकायों में डीएनएफ एवं अन्य सीएसआर की राशि उपलब्ध है, वहां लोहे की कंटीली तार के माध्यम से फेंसिंग कराई जाए। मुक्तिधाम परिसर में पूर्व से निर्मित प्लेटफार्म शेड, बैठक स्थान आदि की मरम्मत निकाय में उपलब्ध राशि या स्वयं के कर राजस्व मद से तत्काल कराना सुनिश्चित करें। मुक्तिधाम में एक हैंडपंप की व्यवस्था की जाए तथा मुक्तिधाम में आवश्यकतानुसार प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी नगरीय निकायों में कम से कम एक मुक्तिधाम शेड एवं प्रतीक्षालय की स्वीकृति दी जाए। इस हेतु प्रस्ताव तत्काल भेजना सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) से मुक्तिधाम परिसर में 2 शौचालय (पुरुष एवं महिला) की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया जाए।

ये है मामला

उच्च न्यायालय के प्रकरण क्रमांक में पिछले साल सितंबर 2025 में मुक्तिधामों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी मामले की सुनवाई करते हुए एक आदर्श मुक्तिधाम में सुविधाएं उपलब्ध कराने के संबंध में आदेश जारी किया था। इस आदेश के परिपालन में राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 49 मुक्तिधामों की व्यवस्था सुधारने के लिए 188 करोड़ रुपए पहली किस्त के रूप में जारी किए हैं। आदेश में कहा गया था कि भारतीय अनुच्छेद-21 के तहत मौलिक अधिकारों में सम्मानजनक मृत्यु और संस्कार का अधिकार शामिल है। यद्यपि पूरे राज्य में मुक्तिधाम वह स्थान है, जिसे सबसे कम प्राथमिकता दी जाती है, का उल्लेख करते हुए पंचायतों, निकायों में स्थित मुक्तिधाम की व्यवस्था सुधार करने निर्देश दिए थे।

खबर संक्षेप

भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का लाभ देने की मांग

महासमुंद। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना में आपत्र से पात्र करने के संबंध में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें मीना डड़सेना पिता स्व. रामप्रसाद डड़सेना ग्राम पचरी ने कहा कि वह परित्यक्ता महिला हैं और जीवनयापन हेतु पूर्णतः मजदूरी पर निर्भर है। उसे मुझे पूर्व में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पंजीयन क्रं 20211116001 393 के तहत वार्षिक सहायता राशि 10000 रुपए प्राप्त हो रहा था। शासन द्वारा भूमिहीन योजना का सत्यापन शासन स्तर पर सत्यापन किया गया। जिसमें त्रुटिवश उसका नाम अपात्र की श्रेणी में दर्ज हो गया है। जबकि, उसके नाम से नाम मात्र भी जमीन नहीं है। ग्राम पंचायत की ओर से इसके सत्यापन में प्रमाणित पंचनामा भी है। महिला ने नियमानुसार भूमिहीन योजना का लाभ प्रदान किए जाने की मांग की है।

मारपीट के दो आरोपियों के खिलाफ जुर्म दर्ज

महासमुंद। नाश्ता ठेला संचालित करने वाले एक व्यक्ति के साथ दो लोगों ने मारपीट कर दी। महासमुंद पुलिस को सुभाषनगर के गणेश जगत ने बताया कि 01 अप्रैल की रात करीबन 10.30 बजे वह अपने दोस्त टुनू के साथ लालदाढ़ी पारा चौक के पास आम रोड में घूमने के लिये गया था। जहां पहले से विक्की मांझी एवं नरेश मांझी उपस्थित थे। इस दौरान उसके दोस्त टुनू ने बताया कि विक्की मांझी एवं नरेश मांझी ने कुछ दिन पहले उसके साथ मारपीट की थी। इस पर जब उसने उक्त लोगों से दोस्त के साथ मारपीट किए जाने को लेकर पूछा तो वे दोनों आरोपी एक राय होकर उसके साथ मारपीट करने लगे। रिपोर्ट पर सिटी कोतवाली में आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 296, 3(5) बीएनएस के तहत जुर्म दर्ज किया गया है।

बैठक : बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन अभियान की समीक्षा

34 संस्थानों का निरीक्षण, चार संस्थानों को नोटिस जारी

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में श्रम विभाग के जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने बाल एवं किशोर श्रम के उन्मूलन के लिए संचालित अभियान की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। इस अवसर पर समिति सदस्य जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि साहू, जिला शिक्षा अधिकारी विजय कुमार लहरे, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला बाल विकास टिक्वेंद्र जटवार, श्रम पदाधिकारी डीएन पात्र, जिला अग्रणी बैंक मैनेजर अभय पारे सहित सदस्य मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने जिले में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन हेतु बचाव एवं पुनर्वास अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति के नोडल अधिकारी डीएन पात्र ने बताया कि अभियान के दौरान जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स द्वारा संयुक्त रूप से 26 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक विभिन्न विकासखंडों में निरीक्षण किया गया। जिसमें महासमुंद विकासखंड में 13, बागबाहरा में 7, बसना में 5, पिथौरा में 5 तथा सरायपाली में 4 संस्थानों का निरीक्षण किया गया। इस प्रकार जिले में कुल 34 संस्थानों की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 04 संस्थानों में बाल श्रम निषेध संबंधी सूचना पटल प्रदर्शित नहीं पाए जाने पर संबंधित प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को एक माह तक विद्यालय से अनुपस्थित रहने वाले बच्चों की स्थिति की जानकारी श्रम विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बालक एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) नियम 2017 की धारा 2बी(2) के तहत उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार ऐसे बच्चों की संख्या निरंक है।

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बाल श्रम उन्मूलन हेतु नियमित निरीक्षण जारी रखें तथा सभी प्रतिष्ठानों में बाल श्रम निषेध सूचना पटल अनिवार्य रूप से प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने के लिए सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए।

भाजपा की विचारधारा ने राजनीति को नई दिशा दी

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

सांसद रूपकुमारी चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस केवल एक राजनीतिक दल का वार्षिक उत्सव भर नहीं है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र में विचारधारा, संगठन और राष्ट्रनिष्ठा की उस परंपरा का स्मरण है, जिसने समय-समय पर राजनीति को नई दिशा दी है।

यह अवसर आत्ममंथन का भी है यह समझने का कि किसी भी दल की वास्तविक शक्ति उसके नेताओं या चुनावी सफलताओं में नहीं, बल्कि उसकी मूल विचारधारा में निहित होती है। भारतीय राजनीति में विचारधारा के महत्व को यदि समझना हो, तो पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के योगदान को स्मरण करना आवश्यक है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे का उद्घोष केवल एक राजनीतिक नारा नहीं था, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का स्पष्ट दृष्टिकोण था। वहीं 'एकात्म मानववाद' और 'अंत्योदय' ने यह स्थापित किया कि विकास का वास्तविक अर्थ समाज के अंतिम

व्यक्ति तक समृद्धि पहुंचाना है। समय के साथ इस विचारधारा को व्यवहार में उतारने का कार्य अनेक नेताओं ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने मर्यादित और समावेशी राजनीति की परंपरा को मजबूत किया, जबकि लालकृष्ण आडवाणी ने संगठन को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्रों में संगठन को वैचारिक और संरचनात्मक मजबूती प्रदान की।

वर्तमान परिदृश्य में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक छवि में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" का मंत्र यह संकेत देता है कि समावेशी विकास ही स्थायी प्रगति का आधार हो सकता है। वहीं अमित शाह की संगठनात्मक रणनीति ने राजनीतिक कार्यप्रणाली को नई परिभाषा दी है। क्षेत्रीय स्तर पर भी यह विचारधारा प्रभावी रूप से परिलक्षित होती है। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लागू जनकल्याणकारी योजनाओं ने यह सिद्ध किया कि जब नीति और नीयत स्पष्ट हो, तो विकास की धारा अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकती है। हालांकि, स्थापना दिवस जैसे अवसर केवल उपलब्धियों के उत्सव तक सीमित नहीं रहने चाहिए। यह समय है यह प्रश्न पूछने का कि क्या राजनीति आज भी विचारधारा-प्रधान बनी हुई है, या वह केवल सत्ता-प्राप्ति का माध्यम बनती जा रही है? किसी भी लोकतंत्र की मजबूती इस बात पर निर्भर करती है कि उसके राजनीतिक दल अपने मूल सिद्धांतों के प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं।

छिंद के पत्तों से मिल रहा है महिलाओं को रोजगार

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

जैसे ही गर्मी का मौसम दस्तक देता है, वैसे ही जिले के ग्रामीण अंचलों में छिंद (खजूर) के पेड़ों की उपयोगिता बढ़ जाती है। इसके मजबूत और टिकाऊ पत्तों से घरेलू उपयोग के लिए झाड़ू तैयार किए जा रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं और कारीगर इन पत्तों को सुखाकर पारंपरिक तरीके से झाड़ू बनाते हैं, जो सफाई के लिए काफी उपयोगी और टिकाऊ होते हैं। स्थानीय बाजारों में इन झाड़ुओं की कीमत 20 से 30 रुपये के बीच है, जिससे आम लोगों को सस्ती दर पर आवश्यक सामग्री

मिल रही है। इस कार्य से ग्रामीण परिवारों, विशेषकर महिलाओं को रोजगार का अवसर मिल रहा है। कम लागत में तैयार होने वाले ये झाड़ू उनके लिए आय का एक महत्वपूर्ण जरिया बनता जा रहा है।

गौरतलब है कि आधुनिक समय में जहां एक ओर बाजार में महंगे प्लास्टिक और मशीन से बने उत्पादों की भरमार है, वहीं दूसरी ओर छिंद से बने ये पारंपरिक उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में भी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस प्रकार, छिंद का पेड़ रोजगार और पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी अपनी उपयोगिता साबित कर रहा है।

झंडा फहरा कर मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

भाजपा मंडल छुईपाली के ग्राम छुईपाली में भाजपा भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस मनाया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हमारे संघर्ष, संकल्प और सेवा की भावना का प्रतीक है। डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देशवासियों के लिए न्याय, विकास और समृद्धि का सपना देखा और पार्टी की नींव रखी। उपाध्याय ने 'एकात्म मानववाद' के मार्ग से राष्ट्र और समाज की उन्नति का संदेश दिया, जो आज भी हमारी राजनीति और कार्यों की दिशा तय करता है।

स्थापना दिवस हमें याद दिलाता है कि पार्टी केवल संगठन नहीं, बल्कि एक आदर्श और उत्तरदायित्व है। आज का मुख्य आकर्षण भाजपा प्रतीक चिन्ह का ध्वजारोहण हमारे एकजुटता और सेवा के संकल्प का प्रतीक है। आइए हम सभी मिलकर इस दिन को यादगार बनाएं और पार्टी की गरिमा को ऊंचाईयों तक पहुंचाने में सहयोग दें। हमारी एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। स्थापना दिवस पर महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष पुष्पलता चौहान, मंडल अध्यक्ष अनिल साहू, महामंत्री संजय प्रधान, धनिराम पटेल, उपाध्यक्ष नीलांबर नायक, दयानिधि जाल, मंत्री नृपराज रावल, पिछड़ा मोर्चा के जिला मंत्री रमेश नायक, अंतराम बिशी, प्रोजेक्ट प्रधान, वेद प्रकाश नायक, हितेश यादव, घनश्याम भोई,

कलेक्टर ने जनदर्शन में सुनी लोगों की समस्याएं, 110 आवेदन मिले

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जनदर्शन में जिले के जनसामान्य की समस्याएं सुनी। कलेक्टर लंगेह ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को प्राप्त सभी आवेदनों को प्राथमिकता के साथ शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आवेदनों का अवलोकन कर नियमानुसार पात्र हितग्राहियों को शासकीय योजनाओं से लाभान्वित करने कहा। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को उनके विभाग से संबंधित आवेदन प्रदान कर शीघ्र निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। जनदर्शन में कुल 110 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में बिरकोनी महासमुंद निवासी पूर्णिमा

सोनवानी ने मनरेगा जॉब कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किया। जिसका त्वरित निराकरण जनदर्शन में ही हुआ, इसके लिए उन्होंने कलेक्टर लंगेह का धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके अलावा तुमगांव निवासी प्रदीप सिंह ठाकुर ने वन अधिकार पट्टा दिलाने हेतु, बागबाहरा निवासी कुलेश्वरी शुक्ला ने महतारी वंदन का लाभ दिलाने, खल्लारी निवासी परमानंद साहू ने श्रम कार्ड बनाने हेतु, ग्राम नवागढ़ सरायपाली निवासी प्रहलाद पटेल ने अपने किडनी रोग के लिए मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना अंतर्गत इलाज हेतु आवेदन किया। इसी तरह ग्राम केशवा निवासी संतोषी साहू ने राशन कार्ड संबंधी त्रुटि हेतु, ग्राम भोरिंग निवासी परमेश्वरी साहू ने दीनदयाल भूमिहीन मजदूर योजना की राशि दिलाने हेतु, खल्लारी निवासी दुर्गेश साहू ने नल जल मित्र कार्यक्रम में प्रशिक्षण करने हेतु, ग्राम जुनवानी निवासी दीपक साहू ने डिजिटल फसल सर्वेक्षण की राशि भुगतान हेतु आवेदन किए। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना, पीएम आवास, अवैध अतिक्रमण, सीमांकन, लम्बित राशि भुगतान संबंधी आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार मौजूद रहे।

पुश्तैनी शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश पीड़िता ने जनदर्शन में लगाई न्याय की गुहार

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

जिला मुख्यालय में आयोजित जनदर्शन कार्यक्रम में मंगलवार को जमीन विवाद से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। महासमुंद की निवासी सोहागाबाई ने कलेक्टर को आवेदन सौंपकर अपनी पुश्तैनी कब्जे वाली शासकीय भूमि को भू-माफियाओं और स्थानीय दबंगों से बचाने की मांग की है। मामला ग्राम मोहबा, तहसील कोमाखान का है।

आवेदिका सोहागाबाई पिता अमरू, जाति सहिस के अनुसार, नेशनल हाईवे 353 से लगी शासकीय भूमि पुराना खसरा नंबर 301/1 पर उनके परिवार का वर्ष 1978 के पहले से शांतिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है। आवेदिका ने बताया कि इस भूमि को उनके नाना, स्वर्गीय सुपेत, बोया करते थे। इसी जमीन पर कृषि कार्य करके उनके परिवार का भरण-पोषण होता है। उनके नाना ने वर्ष 1978-79 में तत्कालीन रायपुर कलेक्टर के समक्ष इस भूमि का पट्टा प्राप्त करने हेतु आवेदन भी प्रस्तुत किया था,

जो वर्तमान तक लंबित है। पट्टा न मिलने के बावजूद, कानूनी रूप से काबिज होने के कारण यह उनकी आजीविका का एकमात्र साधन है। सोहागाबाई का आरोप है कि वर्तमान में गांव के ही कुछ प्रभावशाली व्यक्ति उनकी इस पैतृक कब्जे वाली जमीन पर जबरन अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। आवेदिका ने ग्राम मोहबा निवासी धरम पिता भोकलू पांडे, श्यामलाल, मानिकराम, सालिकराम पिता भगेला यादव, भोजराम पिता देवनाथ चंद्राकर और मेघनाथ पिता नंदलाल गांड़ा पर जमीन हड़पने के प्रयास का आरोप लगाया है।

पीड़िता की मांग: जनदर्शन में सौंपे गए पत्र के माध्यम से सोहागाबाई ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उनके पूर्वजों के समय से काबिज इस भूमि से अवैध अतिक्रमणकारियों को हटाया जाए। जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। उनकी आजीविका के साधन कृषि भूमि को सुरक्षित किया जाए।

नेशनल लोक अदालत 9 मई को अधिकारियों की ली तैयारी बैठक

महासमुंद। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार आगामी 09 मई शनिवार को जिला न्यायालय तथा सभी तालुका स्थित न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रभारी सचिव एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चेतना ठाकुर ने बताया कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों में कमी लाने के उद्देश्य से तथा प्रभावित पक्षकारों को त्वरित, सस्ता एवं सुलभ न्याय प्रदान करने की दिशा में नेशनल लोक अदालत एक प्रभावशाली कदम है। जिला न्यायालय सहित सभी तालुका स्थित न्यायालयों में खंडपीठों का गठन कर विभिन्न प्रकरणों तथा प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा। इस संबंध में जिला न्यायालय स्थित वीडियो कांफ्रेसिंग कक्ष में प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिता डहरिया ने प्री-लिटिगेशन प्रस्तुत करने वाले विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबधकों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों की बैठक ली गई।

इस अवसर पर विशेष रूप से प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संघपुष्पा भतपहरी उपस्थित थे। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उपस्थित बैंक के पदाधिकारियों, प्रबंधकों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों को लोक अदालत में लंबित प्रकरणों को अधिक से अधिक पंजीबद्ध कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही पूर्व 14 मार्च 2026 को आयोजित लोक अदालत में रखे गए प्रकरणों तथा उन पर गई निराकृत प्रकरणों की कार्यवाहियों पर भी समीक्षा की गई। पुराने एवं लंबित प्रीलिटिगेशन संबंधी प्रकरणों को आगामी 9 मई को आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के पूर्व विधिवत पंजीयन उपरांत संबंधित पक्षकारों का प्रकरण को लोक अदालत के खंडपीठ के माध्यम से निराकरण करा सकते हैं। बैठक में छग स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के सहायक अभियंता मुक्तेश्वरी साहू आदि मौजूद रहे।

गांव-गांव में किया जा रहा है गायत्री महायज्ञ का आयोजन

हरिभूमि न्यूज ⏭ महासमुंद

अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देशभर में साधना एवं यज्ञीय कार्यों का व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। गायत्री परिवार महासमुंद द्वारा गांव-गांव संपर्क अभियान संचालित कर 1, 3, 5 एवं 9 कुण्डीय गायत्री महायज्ञों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही प्रत्येक परिजन को नियमित स्वाध्याय एवं साधना अनुष्ठान के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य मानव में देवत्व का उदय एवं धरती पर स्वर्ग का अवतरण के दिव्य संदेश को जन-जन तक पहुंचाना है। संध्या कालीन दीप महायज्ञ के साथ नवयुग के सत्संकल्प के 18 सूत्रों का वाचन कराया जा रहा है। ग्राम पंचायतों में सामूहिक बैठकों के माध्यम से इन सूत्रों के प्रचार-प्रसार का कार्य भी

किया जा रहा है। इसी कड़ी में गायत्री शक्ति पीठ के महिला मंडल द्वारा कुकरा (आरंग), सिरपुर, चकरदा (सरायपाली), मोरधा, कोलपदर, लाफिन खुर्द, पासिद आदि गांवों में पांच कुंडीय गायत्री महायज्ञ, विभिन्न संस्कार एवं दीप यज्ञ कराया गया। इसके अतिरिक्त जिला जेल महासमुंद में भी साधना एवं स्वाध्याय विषय पर एक विशेष कार्यशाला का आयोजन किया गया। साथ ही घर-घर में 24 हजार मंत्रों का लघु अनुष्ठान भी कराया जा रहा है। अब तक लगभग 40 घरों में यह साधना पूर्ण की जा चुकी है। गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने बताया कि यह अभियान निरंतर जारी रहेगा और अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

मिशन गांव चलो अभियान के तहत पंचायत एवं बूथ कमेटियों का गठन

सरायपाली। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 'मिशन गांव चलो अभियान' के अंतर्गत संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त एवं सक्रिय बनाने हेतु व्यापक स्तर पर पंचायत एवं बूथ कमेटियों के गठन की प्रक्रिया निरंतर जारी है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मार्गदर्शन एवं जिलाध्यक्ष द्वारकाधीश यादव तथा विधायक चातुरी नंद के निर्देशन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष तेजराम पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस की टीम गांव-गांव पहुंचकर संगठन को मजबूती प्रदान करने और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां सौंपने का कार्य कर रही है। इसी क्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली ग्रामीण के अंतर्गत विभिन्न ग्राम पंचायतों में संगठन विस्तार का महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया गया। अभियान के तहत ग्राम कुटेला, जोगनीपाली, पंधी, बिलाईगढ़, माधोपाली सहित जंगलबेड़ा, राजाडीह, भालुकोना, पजरापाली, गिधामुड़ा, बेलडीह, सरायपाली, लमकेनी, तोषगांव, गोहरापाली, अतर्ला, पंडापारा एवं तोरेसिंघा में पंचायत कमेटियों एवं बूथ कमेटियों का गठन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से संवाद स्थापित करते हुए संगठन की नीतियों एवं विचारधारा से अवगत कराया तथा अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस संगठन से जोड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सरायपाली ग्रामीण के प्रमुख पदाधिकारी विजय नायक, परसु चौहान, कैलाश तांडी, शिवलाल नायक, मंडल अध्यक्ष संजय प्रधान, प्रदीप कर, शरद यादव, चरण तांडी, पिंकू पैसायट, श्यामलाल बारीक, जयकृष्ण प्रधान, गिरधारी ओगरे, घसिया यादव, तोरन सिंह यादव, वृंदा जगत, हीरालाल प्रधान, विनय पटेल, सुशील प्रधान, मदन साहू सहित सभी गांवों के कांग्रेसजन सक्रिय रूप से शामिल हुए। "मिशन गाँव चलो अभियान" के माध्यम से कांग्रेस संगठन को बूथ स्तर तक सुदृढ़ करने, आमजन से सीधा संवाद स्थापित करने एवं आगामी चुनावों के लिए मजबूत आधार तैयार करने की दिशा में यह अभियान मील का पत्थर साबित हो रहा है।

खबर संक्षेप

महतारी वंदन योजना के हितग्राहियों का 131 केंद्रों में ई-केवाईसी जारी

महासमुंद। महतारी वंदन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने जिले में 131 विभिन्न केंद्रों में शिविर का आयोजन किया गया है। आयोजित शिविर के माध्यम से पात्र विवाहित महिलाओं का ई-केवाईसी किया जा रहा है। शिविरों में हितग्राहियों की पहचान बायोमेट्रिक सिस्टम और आधार कार्ड के माध्यम से की जा रही है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों तक ही पहुंचे। बड़ी संख्या में महिलाएं इन शिविरों में पहुंचकर अपने दस्तावेजों का सत्यापन करा रही हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों तथा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मौके पर ही महिलाओं को ई-केवाईसी की प्रक्रिया, आवश्यक दस्तावेज और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जा रही है। जिले में 3 लाख 3 हजार 808 हितग्राहियों का ई-केवाईसी किया जाना है। इसके लिए 367 सीएससी सेंटरों को आईडी जारी किया गया है। विभिन्न चॉइस सेंटरों के माध्यम से ई-केवाईसी का कार्य जारी है।

पंचमुखी हनुमान मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा व मारुति यज्ञ हुआ

बिरकोनी। बरबसपुर मोड़ बिरकोनी में पंचमुखी हनुमान मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा एवं मारुति यज्ञ हुआ। त्रिदिवसीय अनुष्ठान महाआरती एवं महाप्रसादी वितरण के साथ हुआ। इस अवसर पर सरपंच चंदन चंद्राकर, जिला पंचायत सदस्य सृष्टि अमर चंद्राकर, नगर पंचायत महासमुंद निखिलकांत साहू, ब्राह्मण समाज अध्यक्ष आरंग प्रद्युम्न शर्मा, पंकज शर्मा ने पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृध्दि की कामना की। आचार्यगण पंडित नरेंद्र द्विवेदी, ध्रुव नारायण शुक्ला, राजेश तिवारी, पंकज तिवारी मोहित तिवारी, शिव तिवारी, सूर्य प्रकाश तिवारी की उपस्थिति में प्राण-प्रतिष्ठा यज्ञ का आयोजन हुआ। आयोजक हितेंद्र तिवारी के नेतृत्व में भव्य पंचमुखी हनुमान मंदिर निर्माण किया गया।

चावल उत्सव मनाया गया

महासमुंद। ग्राम खरोरा में चावल उत्सव मनाया गया। इस दौरान सरपंच वीणा कमलेश चंद्राकर, सचिव चंद्रमणि चंद्राकर, पटवारी रामनारायण चंद्राकर, पंचगण व ग्रामीण उपस्थित रहे। सरपंच वीणा चंद्राकर ने कहा कि 7 अप्रैल को चावल उत्सव मनाया गया। जिसमें हितग्राहियों को तीन महीने अप्रैल, मई, जून का राशन एकमुश्त वितरण किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री सड़क योजनाः सानटेमरी में 77 करोड़ रुपए लागत के 44 सड़कों का भूमिपूजन

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत जिले के पिथौरा विकासखंड के ग्राम पंचायत सानटेमरी में सड़क विकास कार्यों का भूमिपूजन किया गया। सांसद रूपकुमारी चौधरी के मुख्य आतिथ्य एवं सरायपाली विधायक चातुरीनंद के विशिष्ट आतिथ्य में कुल 44 सड़कों के निर्माण हेतु भूमिपूजन कार्य किया गया। इन सड़कों की कुल लंबाई 96.495 किलोमीटर है, जिसकी लागत 77 करोड़ 47 लाख 99 हजार रुपए है। भूमिपूजन कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष भीखम सिंह ठाकुर, जनपद पंचायत पिथौरा की अध्यक्ष उषा धृतलहरे, जनपद सदस्य कंवलजीत सिंह छाबड़ा, पुरुषोत्तम धृतलहरे, बिमला बेहरा, सुमीत अग्रवाल, हलधर साहू, अभिमन्यु प्रधान, रमेश अग्रवाल, कैलाश चंद्र अग्रवाल, ग्राम पंचायत सानटेमरी के सरपंच देवेंद्र यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सांसद रूपकुमारी चौधरी ने भूमिपूजन कर विकास कार्यों का शुभारंभ किया। सांसद चौधरी ने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से क्षेत्र के ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी, कृषि उत्पादों के परिवहन में तेजी आएगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य शासन का संकल्प है कि कोई भी गांव विकास से अछूता न रहे। प्रधानमंत्री सड़क

योजना के तहत सरकार का उद्देश्य हर गांव को बेहतर सड़क संपर्क से जोड़ना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक प्रगति सुनिश्चित हो सके। सांसद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इन कार्यों को गुणवत्ता और समय सीमा में पूरा करें, ताकि जनता को इसका शीघ्र लाभ मिल सके। सरायपाली विधायक चातुरीनंद ने विकास के लिए सड़कों को जरूरी बताया और कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण अंचलों में आवागमन की सुलभ सुविधा आवश्यक है। इन सड़कों के निर्माण से निश्चित तौर पर आवागमन सुगम होगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यपालन अभियंता आशीष कुलदीप ने बताया कि जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी और समय सीमा में सड़क निर्माण का कार्य पूरा किया जाएगा। उपस्थित स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने इस पहल को क्षेत्र के विकास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया तथा केंद्र एवं राज्य शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया है।

बैठक : सभी विभाग वार्षिक कार्ययोजना बनाएं, समय में पूर्ण करें कार्य

चावल भंडारण कार्य 13 तक पूर्ण करने कलेक्टर ने दिए निर्देश

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय-सीमा की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जिले में संचालित शासकीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में कलेक्टर लंगेह ने जिले के सभी विभागों के अधिकारियों को शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण करने तथा समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

कलेक्टर ने सभी विभागों को आगामी वित्तीय वर्ष के लिए विस्तृत वार्षिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रत्येक विभाग अपने लक्ष्य निर्धारित कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि यूरिया की बिक्री अनिवार्य रूप से पॉस मशीन के माध्यम से की जाए तथा भंडारण का नियमित भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि अनियमितता पाए जाने पर संबंधितों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कृषि विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जिले के 80 निजी दुकानों में अनियमितता पाई गई है, जिन पर कार्रवाई की जा रही

है। कलेक्टर लंगेह ने सभी कार्यालयों में आधार आधारित उपस्थिति अनिवार्य करने तथा ई-फाइल प्रणाली को शत-प्रतिशत लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है। कलेक्टर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत अप्रैल, मई एवं जून माह के चावल भंडारण की समीक्षा करते हुए 13 अप्रैल तक भंडारण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम को नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। नान (नागरिक आपूर्ति निगम) के अधिकारी ने जानकारी दी कि अप्रैल माह का शत-प्रतिशत भंडारण पूर्ण हो चुका है, मई माह का 221 दुकानों में तथा जून माह का 39 दुकानों में भंडारण किया जा चुका है। जिले में कुल 593 उचित मूल्य की दुकानें संचालित हैं। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी दुकानों में चावल उत्सव अनिवार्य रूप से आयोजित किया जाए।

आकांक्षी ब्लॉक एवं जिले में संचालित संपूर्णता अभियान 2.0 की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी संकेतकों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन संकेतकों में गैप है, उन्हें एक सप्ताह के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने 6 माह से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में नियमित रूप से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत पात्र बच्चों को कक्षा पहली में प्रवेश दिलाने हेतु निर्देश दिए कि सभी निजी विद्यालय निर्धारित नियमों के अनुसार 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश सुनिश्चित करें। यह प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है तथा पारदर्शिता के साथ की जाए। उन्होंने एसडीएम को इसकी नियमित निगरानी करने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी निजी स्कूलों द्वारा नियमों का अनिवार्य पालन किया जाए। जल संरक्षण के लिए मोर गांव मोर पानी अभियान 2.0 के तहत विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने कहा कि अधिक से अधिक सोखता गड्ढे, डबरी, तालाब एवं अन्य जल संरचनाओं का निर्माण कराया जाए। उन्होंने किसानों को खेतों में जल संरक्षण संरचनाएं बनाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा प्रधानमंत्री आवासों में सोखता गड्ढा एवं भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही इस अभियान में जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री घोषणाओं, राजस्व पखवाड़ा, जनगणना, पीएम सूर्यघर योजना, आयुष्मान कार्ड, प्राधिकरण, जनशिकायत एवं लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ हेमंत नंदनवार, अपर कलेक्टर सचिन भूतड़ा, रवि कुमार साहू, अनुविभागीय अधिकारी विभागीय जिलाधिकारी, जनपद सीईओ, नगरीय निकायों के सीएमओ तथा वीसी के माध्यम से ब्लॉक स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कर्मचारियों को केंद्रीय दर का लाभ प्रदान करने नपाध्यक्ष ने लिखा मंत्री को पत्र

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

नगरीय निकाय के कर्मचारियों को नवीन श्रम संहिताओं के अंतर्गत केंद्रीय दर का लाभ प्रदान करने की मांग को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष निखिलकांत साहू ने उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग मंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर कर्मचारियों को तत्काल राहत प्रदान करने की मांग की है।

नपाध्यक्ष ने पत्र में कहा है कि 4 नवीन श्रम कोड के तहत कर्मचारियों को केंद्रीय वेतनमान एवं अन्य लाभ प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है। किंतु, वर्तमान में नगर पालिका एवं नगरीय निकायों के कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। जिससे कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त है।

साहू ने मंत्री से इस महत्वपूर्ण विषय पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश प्रदान करने का निवेदन किया है।

उल्लेखनीय है कि एक दिन पूर्व ही नपा के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने पालिकाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपकर श्रम कानून लागू कर वेतन प्रदान करने की मांग की थी। कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखकर नपाध्यक्ष साहू ने नगरीय प्रशासन मंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांग से अवगत कराया।

अछोला में मनाया गया भाजपा का स्थापना दिवस

महासमुंद। भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस पर जिलेभर में उत्साह और उमंग के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी क्रम में शक्ति केंद्र प्रभारी एवं ग्राम पंचायत अछोला के उपसरपंच, ग्रामीण सेवा सहकारी समिति अध्यक्ष विश्वनाथ धीवर ने अपने निवास पर भाजपा स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने स्थापना काल से ही राष्ट्रवाद, सेवा और सुशासन के सिद्धांतों पर कार्य करते हुए देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हो चुकी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन की वास्तविक ताकत उसके समर्पित कार्यकर्ता होते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत और निष्ठा के बल पर ही पार्टी निरंतर आगे बढ़ रही है। उन्होंने सभी से अपील की कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं, ताकि आम जनता को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने भी पूरे उत्साह के साथ स्थापना दिवस मनाया और संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर क्षेत्र में भाजपा के प्रति उत्साह और एकजुटता का माहौल देखने को मिला।

बरबसपुर में कलश शोभायात्रा के साथ श्रीमद भागवत महापुराण कथा का शुभारम्भ

हरिभूमि न्यूज ▶▶| बिरकोनी

ग्राम बरबसपुर में सोमवार को श्रीमद भागवत महापुराण कथा के साथ महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली गई। बाजार चौक सांस्कृतिक रंगमंच में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का शुभारंभ कलश शोभायात्रा के साथ हुई। कलश शोभा यात्रा राम मंदिर से होकर तालाब के पास से जल अर्पित कर मुख्यमार्ग से होते हुए कलश शोभायात्रा आयोजन स्थल पर पहुंची। गाजे बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने हरे कृष्णा, हरे राम, श्री राधे कृष्ण की जय, जय श्याम गीत गूंजायमान रहा। आयोजकों ने भगवा ध्वज लहराया व चौक चौराहों में आतिशबाजी की गई। धार्मिक गीतों में श्रद्धालु जमकर झूमे वो आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा।

कथा का शुभारंभ करते हुए कथावाचक पंडित रूपनारायण शर्मा व पारायणकर्ता पंडित चंदन प्रसाद उपाध्याय ने पूजा अर्चना की। कथावाचक शर्मा ने भागवत गीता का स्मरण करते हुए बताया कि भगवान श्रीराम के बाद श्रीकृष्ण का युग आया, जो व्यक्ति श्रीराम के चरित्रों को अपने मानस में संजो लेता है। उसकी बेडा पार हो जाता है। भागवत साक्षात भगवान का रूप है। भागवत का प्रत्येक अक्षर का अपना ही अर्थ है। भागवत कथा केवल कथा नहीं, बल्कि प्रेम ग्रंथ है। इस प्रेम ग्रंथ को सुनने के कई नियम है। उन्होंने कहा कि भागवत कथा सुनने से काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या पर नियंत्रण मनुष्य पा सकता है, ये कलियुग नहीं करयुग है। भगवान कहते हैं कि कर्म पर विश्वास रखो तभी कुछ अच्छा प्राप्त होगा। भागवत सप्ताह के प्रत्येक दिन की कथा सुनना जीवनोपयोगी है, जो कलयुग में भगवत प्राप्ति के लिए अत्यंत सरल मार्ग निर्धारित किए गए हैं। भगवान के नाम मात्र का जाप करने से कलयुग में मुक्त पाने का विधान है। इस अवसर हरीश यादव, विष्णु चंद्राकर, चमरू निषाद, रामा यादव, संतोष सेन, संतोष विश्वकर्मा, गजेंद्र साहू, जय साहू, चंद्रिका यादव, रोशन दास, गोविंदा चंद्राकर, गणेश साहू, जितेंद साहू आदि मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री आवास के नाम पर गरीबों की भावनाओं से हो रहा खिलवाड़ : आलोक

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

भाजपा की साय सरकार द्वारा प्रदेश में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने के दावों को खोखला व झूठा बताते हुए राज्य जीव जंतु बोर्ड के उपाध्यक्ष व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री आलोक चंद्राकर ने कहा कि भाजपा के सवा 2 साल के कार्यकाल में 18 हजार आवास भी पूर्ण नहीं हो पाया है। पूर्ववर्ती भूपेश सरकार में जो आवास स्वीकृत हुए थे, उसे भाजपा की साय सरकार अपनी उपलब्धि बताते हुए श्रेय लेने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि, सच्चाई यह है कि वर्तमान में हितग्राहियों को स्वीकृत आवासों की राशि जारी नहीं की जा रही है। अनेक आवास अधूरे पड़े हैं।

> ■ 18 लाख आवास देने वालों के 2 साल के कार्यकाल में 18 हजार आवास भी पूर्ण नहीं हो पाए

पीएम आवास निर्माण के आस में गरीब हितग्राहियों ने मकान तोड़कर निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया है, लेकिन, पहली किस्त के बाद दूसरे व तीसरे किस्त के लिए उन्हें सरकारी दफ्तारों के चक्कर लगाना पड़ रहा है। शहर में ही झूग्गी बस्तियों में स्वीकृत आवासों की स्थिति चिंताजनक है। महासमुंद शहर के सुभाष नगर में दर्जनों आवास 4 महीने पहले स्वीकृत हुए थे। जिनका प्रथम किस्त आने के बाद अब तक दूसरे व तीसरे किस्त की राशि नहीं मिल पाई है।

आलोक ने कहा कि कुछ दिन पूर्व ही जिला पंचायत सभाकक्ष में जिलेभर के पंचायत पदाधिकारियों, सचिवों, सभी जनपद सीईओ की बैठक लेकर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधूरे आवासों को पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। प्रशासन की सारी कार्रवाई केवल कागजों तक ही सीमित है।

हितग्राहियों के घर जाकर करें सर्वे

धरातल पर वास्तविकता से कोसों दूर हैं। यदि, शासन-प्रशासन आवास योजना को लेकर गंभीर हैं, तो हितग्राहियों के घर जाकर सर्वे किया जाना चाहिए। प्रथम, द्वितीय, तृतीय किस्त मिलने के लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, उसके अनुसार समय पर हितग्राहियों को भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

आईटीआई में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन

महासमुंद। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर स्थानीय शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस स्वास्थ्य शिविर में हेल्थ चेक अप के दौरान प्रशिक्षणार्थियों के ब्लड टेस्ट, बीपी जांच सिकलिनटेस्ट और अन्य महत्वपूर्ण जांचें की गईं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों द्वारा जांच उपरांत प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। संस्था के प्राचार्य जीएस साहू एवं एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र कुमार साहू की उपस्थिति में आयोजित इस शिविर में एपीएम धर्मेंद्र भारद्वाज, डॉक्टर गंगेश्वर दीवान, नर्सिंग स्टाफ मनीषा साहू, फार्मासिस्ट पवन साहू एवं लैब टेक्नीशियन प्रमिला राणा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उक्त शिविर में संस्था के सभी कर्मचारियों ने भी अपने स्वास्थ्य की जांच करवाई। कार्यक्रम अधिकारी भूपेंद्र कुमार साहू ने कहा कि शिविर का मुख्य उद्देश्य प्रशिक्षणार्थियों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण की महत्ता को समझाना है।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जिले के 2961 हितग्राहियों को मिल रहा आर्थिक लाभ

हरिभूमि न्यूज ▶▶| महासमुंद

केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आम नागरिकों के लिए ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक प्रभावी कदम साबित हो रही है। इस योजना के माध्यम से देश सहित जिले के आवासीय परिवारों को अपनी बिजली स्वयं उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके अंतर्गत 5 किलोवाट तक के सोलर रूफटॉप सिस्टम पर केंद्र सरकार द्वारा 78,000 रुपए तथा राज्य सरकार द्वारा 30,000 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। इस योजना से आम जनता को आर्थिक राहत मिलने के साथ ही अक्षय ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में अब तक महासमुंद जिले के 2961 हितग्राही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। अब तक कुल 7779 नागरिकों ने इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन किया है। सभी हितग्राहियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का आभार जताया है और लोगों से अपील की है कि हर घर को इस योजना से जुड़ना चाहिए। आज हम सिर्फ उपभोक्ता नहीं, बल्कि बिजली उत्पादक और पर्यावरण रक्षक भी बन सकते हैं।

इमली भाठा निवासी उषा साहू ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना से उन्हें नियमित और सस्ती ऊर्जा मिल रही है। इससे बिजली बिल में काफी कमी आई है और परिवार की आर्थिक बचत भी बढ़ी है।

इसी तरह महासमुंद निवासी यामिनी यदु ने कहा कि इस योजना के माध्यम से सोलर पैनल लगवाने में शासन से सब्सिडी मिली, जिससे खर्च कम हुआ। अब घर में दिनभर बिजली उपलब्ध रहती है और अतिरिक्त बिजली ग्रिड में देने से भी लाभ मिल रहा है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित हितग्राही कुम्हार पारा निवासी गेंद लाल साहू ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उनके घर की छत पर सोलर पैनल लगने से अब बिजली बिल लगभग शून्य हो गया है।

पहले हर महीने बिजली बिल की चिंता रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा से घर की जरूरतें पूरी हो रही इसी तरह वर्धमान नगर महासमुंद निवासी घनश्याम ध्रुव ने कहा कि सोलर पैनल लगने के बाद बिजली कटौती की समस्या खत्म हो गई है। अब घर में पंखा, कूलर और अन्य उपकरण आसानी से चल पाते हैं। उन्होंने बताया कि यह योजना पर्यावरण के लिए भी लाभकारी है। सौर ऊर्जा के उपयोग से बिजली की बचत हो रही है और घर का मासिक खर्च भी कम हुआ है।